POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2021/अंक 03

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 मार्च, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट प्रस्तुत किया। कोरोना महामारी से सबक लेकर वित्तमंत्री ने आपदा को एक अवसर माना है।

बजट में जन स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। कृषि क्षेत्र को ग्रोथ का इंजन मानते हुए पेट्रोल, डीजल सहित 12 चीजों की कस्टम ड्यूटी पर कृषि सेस लगाया है। इस सेस से होने वाली कमाई कृषि के ढांचागत विकास को मजबूती देगी। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से बजट में और भी कई कदम उठाए गए हैं।

इसके साथ ही वित्तमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ते हुए विश्वस्तरीय बनाने, उच्च शिक्षा में अनुसंधान पर जोर देने, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने जैसी कई घोषणाएं बजट में शामिल हैं।

मेरा मानना रहा है कि बजट घोषणाओं को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।

कोरोना ने दी नसीयतः मजबूत होगा सेहत का तंत्र

इस बार आम बजट में जन स्वास्थ्य को खास अहमियत दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले बजट के मुकाबले 137 फीसदी ज्यादा है। इससे 6 वर्ष के लिए 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' संचालित की जाएगी जिस पर 64 हजार 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

माना जा रहा है कि इससे सेहत के तंत्र को मजबूती मिलेगी। आमजन तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए पहली बार 30 हजार करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड का भी प्रावधान बजट में रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से बने आर्थिक हालात को देखते हुए यह एक अच्छी पहल है।

किसान को माना ग्रोथ इंजनः आय को दोगुना करने का लक्ष्य

केंद्रीय बजट में सबसे बड़ा लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इसके लिए कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और इससे जुड़े कामों के लिए बजट में 2 लाख 83 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक लाख 48 हजार 301 करोड़ रुपए इस बार कृषि एवं कृषक कल्याण के लिए खर्च होंगे। किसानों को 16 लाख 50 हजार करोड़ रुपए के ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था में भी सुधार किया है, जिससे किसानों को सभी प्रकार की जिसों के मामले में उत्पादन लागत का डेढ़ गुना कीमत मिल सके। दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिए भी सरकार योजना लाएगी। जैविक खेती के लिए ऑनलाइन बाजार को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि उत्पादों की सही कीमत मिले इसके लिए किसान रेल कोच व कृषि उड़ान योजना शुरू होगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021-22 तक के लिए बढ़ाया जाएगा।

आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं

आम करदाता को आशा थी कि इस बार बजट में आयकर स्लैब बदलेगी। इससे नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। लेकिन आयकर की स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। लघु बचत योजनाओं में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैंक की बचत योजनाओं को भी उनके प्रबंधन पर छोड़ दिया गया है। आम आदमी को किसी भी तरह के डिडक्शन में राहत नहीं मिली हैं। हालांकि, 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने में छूट दी है। लेकिन इसके लिए वे ही पात्र होंगे जिनकी आय पेंशन और बैंक ब्याज से हो रही है।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2020

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 39 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2020 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह हैः

'कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2020 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2021 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोनः 0141-2282821, फैक्सः 0141-2282485, 4015395

ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को दी अहमियत

बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 93 हजार 224 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों के तहत 15 हजार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। ये स्कूल, दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनेंगे। देश में भागीदारी से सौ नए सैनिक स्कूल भी स्थापित होंगे। बुनियादी शिक्षा के साथ अब भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कौशल और कुशलता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

पूर्व में घोषित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग को इस साल कानूनी जामा पहनाया जाएगा। जो एक अम्ब्रेला निकाय के रूप में काम करेगा। देश में नवाचार के लिए नौ शहरों में अम्ब्रेला संस्थाए बनाई जाएंगी। इससे उच्च शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। शिक्षा मिशन के लिए 34 हजार 300 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात दी गई है। आयोग के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय मदद भी दी जाएगी। खासतौर पर उच्च शिक्षा में अनुसंधान पर जोर रहेगा।

अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास

कोरोना संक्रमण से बेहाल देश की अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जहां बड़े कल कारखानों को बजट में सम्बल प्रदान किया गया है, वहीं छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बड़ा पिटारा भी खोला गया है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के तहत 64 हजार करोड़ से भी ज्यादा राशि रखी गई है। वहीं 40 हजार करोड़ रुपए गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और 15 हजार 700 करोड़ रुपए का प्रावधान लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए किया गया है।

यह प्रावधान पिछले साल से दोगुना है। इससे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक की कंपनी को छोटे उद्योग में रखा गया है। बड़े उद्योगों की बात करे तो 3 लाख 5 हजार 984 करोड़ रुपए पांच साल में केवल पॉवर सेक्टर पर खर्च किए जाएंगे।

हर घर जल और बिजली की सहूलियत

जल जीवन मिशन और ऊर्जा पर अगले पांच वर्षों की कार्ययोजना में 6 लाख 92 हजार 984 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल जीवन मिशन पर 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा और विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट प्रावधान है।

ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत बहुत बेहतर काम हो रहा है। इसे देखते हुए अब इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में भी हर घर नल, हर घर जल योजना को शुरू किया जाएगा। योजना के तहत पानी के सरकारी कनेक्शन से वंचित परिवारों को सरकार कनेक्शन देगी।

ऊर्जा क्षेत्र में अब उपभोक्ता को मनचाही विद्युत वितरण कंपनी को चुनने की आजादी होगी। विद्युत तंत्र को सुधारने की दिशा में बड़ा काम होगा। इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर अमल करते हुए देश में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की स्थापना की जाएगी।

हुनर से पनपेंगे रोजगार के अवसर

कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के महापलायन पर नजर रखते हुए केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टल की घोषणा की गई है। जिसके जरिए विशाल श्रम शक्ति की सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें कौशल विकास, आवास और बीमा जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कौशल विकास में सरकार अन्तरराष्ट्रीय सहयोग पर आगे बढ़ेगी।

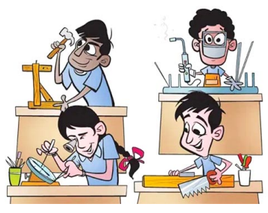

जापान और अन्य देशों से कुशलता व उन्नत प्रशिक्षण के लिए सहयोग लिया जाएगा। पोर्टल से पहले राजस्थान इसकी पहल कर चुका है। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए चुनिंदा 13 सेक्टरों के लिए 1.97 लाख करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मनरेगा का बजट भी 15.8 फीसदी बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने शिपिंग सेक्टर में सीधे तौर पर 1.50 लाख युवाओं के लिए नौकरी की आशा जताई है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021

जैसा कि विदित है 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय 'प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण से निपटना' है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के विरूद्ध एक विश्वव्यापी उपभोक्ता आंदोलन होगा।

वैसे तो प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में एक अत्यधिक उपयोगी सामग्री बन गया है, लेकिन इसके बढ़ते उपभोग एवं उत्पादन हमारे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ जैव विविधता पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अब चूंकि यह एक वैश्विक चुनौती बनता जा रहा है, इसलिए इससे निपटने के लिए समन्वित वैश्विक समाधान की आवश्यकता है।

उपभोक्ता संगठन जनसाधारण को निरन्तर इस चुनौती से निपटने के लिए प्रोत्साहित कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः सभी उपभोक्ता संस्थाएं इस अवसर पर अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

स्वच्छ भारत मिशनः साफ आबोहवा

केंद्रीय बजट में स्वच्छता और पोषण को खास तवज्जो दी है। क्योंकि, स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत का निर्माण संभव है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर वर्ष 2021 से 2026 तक 5 वर्षों में एक लाख 41 हजार 668 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्लम मैनेजमेंट, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट और शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर खास फोकस रहेगा।

इसके साथ ही दस लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों की हवा को साफ करने पर 2 हजार 217 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे लोगों को स्वच्छ आबोहवा मिल सकेगी। वित्तमंत्री ने 64 हजार 184 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन योजना का भी ऐलान किया है। यह योजना नेशनल हैल्थ मिशन से अलग होगी।

बाल विकास एवं महिलाओं पर फोकस

केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशिष्ट योजनाओं के लिए 28 हजार 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्टार्टअप इण्डिया के तहत महिलाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 9 करोड़ तक कर दिया गया है। रात्रि शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर सकेंगी। स्कूलों में बच्चों के मिड-डे मील का बजट 11 हजार 500 करोड़ रुपए किया गया है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के प्रयासों को तेज किया जाएगा।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पाजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर